

- संविधान दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर प्रदेशभर में हुए आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- देश का संविधान सबसे विस्तृत और सशक्त।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पैन परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रयागराज-मानिकपुर रेल लाइन सहित रेलवे की तीन परियोजनाओं को भी मिली स्वीकृति।
- सम्मेलन में हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य। कल से खुल गये स्कूल और बाजार।
- सीआईएससीई का परीक्षा कार्यक्रम जारी। दसवीं की परीक्षा अक्टूबर फरवरी से सत्ताइस मार्च और बारहवीं की परीक्षाएं तेरह फरवरी से पांच अप्रैल तक चलेंगी।

संविधान दिवस की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। राज्य सरकार ने इस अवसर पर कल से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह छब्बीस नवम्बर, दो हजार पच्चीस तक देशभर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान है। संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान सभा में हुई विभिन्न सार्थक बहसों आज भी हम सबका मार्ग दर्शन करती है।

भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में यह डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे। भारत की यात्रा के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है वह डिबेट मूल रूप से नहीं उसका एक निचोड़ जो लेकेआना था वो भारत के संविधान के रूप में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी ने देश को दिया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 'संविधान से आदर्श और मूल्य' विषय पर आयोजित वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

उधर, लखनऊ में केन्द्रीय संचार ब्यूरो ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि समानता और न्याय के मामले में भारत का संविधान अमेरिका से भी आगे है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हापुड, संतकबीर नगर, सुल्तानपुर और मऊ सहित कई जिलों में संविधान दिवस पर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक दिन पूर्व हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की पैन परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी गई। इस परियोजना पर एक हजार चार सौ पैंतीस करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस चरण में पूरे मौजूदा तंत्र को संवर्धित किया जाएगा और पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैन के दूसरे चरण में मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन नम्बर बने रहेंगे।

एविजस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वह कंलीट नए तरीके से की जाएगी। कॉमन बिजनेस आई डेंटिफायर का मिशन इसमें प्रयास किया जाएगा एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा। इसमें बहुत फॉक्स दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो हजार चार सौ इक्यासी करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और एक राष्ट्र एक सदस्यता को भी मंजूरी दे दी गयी है। वहीं, आर्थिक मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर लगभग सात हजार नौ सौ सत्ताइस करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में प्रयागराज-मानिकपुर रेल लाइन, मनमाड-जलगांव रेल लाइन और भुसावल-खंडवा रेल लाइन शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मनमाड-जलगांव परियोजना से महाराष्ट्र के बंदरगाहों से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी।

एक सौ साठ किलोमीटर का यह रूट है। दो हजार सात सौ 73 करोड़ रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई, कोलकाता और मुंबई से वाराणसी यह दोनों के दोनों रूट इससे डीकन्जस्ट हो जाएंगे और यहां की कैपेसिटी बढ़ेगी। नई गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। कंटेनर जल्दी से तेजी से भुव होंगे।

बैठक में अटल इनोवेशन मिशन-एआईएम को इकतीस मार्च, दो हजार अट्ठाइस तक जारी रखने को भी स्वीकृति दी गयी है।

सम्मेल में हुई हिंसा के बाद अब वहां स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। कल से स्कूल और बाजार खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तीस नवम्बर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह बताया कि पुलिस उपद्रवी तत्वों की पहचान कर रही है। मामले से जुड़े साक्ष्य भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें।

सम्मेल में अब हालात सामान्य हैं। स्कूल भी खुले हुए हैं। सामान्य जनजीवन आम तौर पर चल रहा है। पुलिस द्वारा जो उपद्रवी तत्व हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। उससे पूर्व लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है लोगों से सहयोग भी मिल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण अफवाहों के कारण किसी तरीके की घटना न घटित हो और लोग अफवाहों पर ध्यान न दे इसलिए भी लोगों से बातचीत जारी है तो फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड सी.आई.एस.सी.ई. ने दसवीं-बारहवीं-दो हजार पच्चीस का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा तेरह फरवरी से शुरू होकर पांच अप्रैल तक और दसवीं की परीक्षा अक्टूबर फरवरी से शुरू होकर सत्ताइस मार्च तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि परिणाम मई में आने की संभावना है।

प्रदेश के स्टाम्प और निबंधन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कल यूपी में पहली बार शुरू हुए ऑनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का वाराणसी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने कहा कि अब कोई भी सौ रुपए तक के स्टाम्प खुद ही प्रिंट कर सकता है। अभी ये व्यवस्था सौ रुपए तक का स्टाम्प के लिए की गई है। इस व्यवस्था के तहत रोजाना इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, सामान्य ऋण समझौता आदि आसानी से तैयार किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ तैयारियों की जायजा लेने के साथ ही महाकुंभ के लिये दो सौ अड़तीस करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ-साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का अनावरण भी शामिल है।

प्रदेश में खरीफ क्रय के अन्तर्गत एजेंसियों द्वारा अब तक सात लाख अट्ठाइस हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष की तुलना में अब तक एक लाख उन्चास हजार मीट्रिक टन अधिक है। वर्ष दो हजार तेइस-चौबीस में पच्चीस नवम्बर तक एजेंसियों द्वारा पांच लाख उन्चासी हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुयी थी। किसानों को अब तक एक हजार चार सौ चौंसठ करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।

प्रदूषण अधिक हो जाने की वजह से बन्द चल रहे स्कूलों को लेकर गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने अब नर्सरी से कक्षा बारह तक के स्कूलों को हाईब्रिड मोड पर खोलने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिया है कि नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक के स्कूल हाईब्रिड मोड में खोले जाएं। यानी प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रबंधन स्कूल खोलने का निर्णय ले सकता है। जहां प्रदूषण कम होगा वहां स्कूल खोले जा सकते हैं और यदि कहीं प्रदूषण ज्यादा है तो वहां स्कूल बन्द रखे जायेंगे और ऑनलाइन क्लासेज के जरिये पढ़ाई करायी जायेगी। गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने भी इसी तरह का आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन को हाईब्रिड मोड पर स्कूल चलाने की हिदायत दी है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक के दो हजार सात सौ दो पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। इसके लिये तेइस दिसम्बर से बाइस जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। इसमें संशोधन उन्तीस जनवरी तक किया जा सकेगा।
